

## उपासना स्थल अधिनियम, 1991

### प्रलिस के लयः

उपासना स्थल (वशष प्रावधान) अधनलडड, 1991

### डेन्स के लयः

डरतीय संवधलन, उपासना स्थल (वशष प्रावधान) अधनलडड, 1991, संबंघतल प्रावधान

### चरुा डें कुडुडु?

**डरत के सरवुओओ नुडरडरलडड** ने **उपासना स्थल अधनलडड, 1991** की वेधता के डरडले कु सुथगतल करते हुड केंडर कु इस डरडले डर अपना रुख सुडुडु करने के लयड 31 अकुतुडर, 2023 तक का डडड दडरड है

### उपासना स्थल अधनलडड:

#### डररुडडड:

- ड यह कुसी डी उपासना स्थल के रूडरंतरण कु डरतडडधतल करने और उसके धररुडड सुवरूड के ररखरखरव और उससे संबंघतल डर उसके आनुडंगकु डरडलु के लयड एक अधनलडड के रूड डें वरणतल कडरड डरड है डरसा कु डरड 15 अगसुत, 1947 कु थर ।

#### अधनलडड के डरडुख प्रावधान:

##### डररुडरंतरण डर रोक (धरर 3):

- ड यह धररर कुसी डी उपासना स्थल के डरवररुतन डर रोक लगरने का प्रावधान करतल है अरुथर कु डी वुडकुतल कुसी डी धररुडड संडररुदरड डर उसके कुसी वरुग के उपासना स्थल कु उसी धररुडड संडररुदरड के कुसी डरनलन वरुग डर कुसी डरनलन धररुडड संडररुदरड डर उसके कुसी वरुग के उपासना स्थल डें डरवररुतल नरुड करेगा ।

##### धररुडड डररुकुतल का ररखरखरव (धरर 4-1):

- ड यह डुषणर करतल है कु 15 अगसुत, 1947 तक असुततलव डें आड उपासना स्थलु की धररुडड डररुकुतल डररुववतु डनी रहेगी ।

##### लंबतल डरडलु का नवरररण (धरर 4-2):

- ड इसडें कहर डरड है कु 15 अगसुत, 1947 कु डुडुड कुसी डी उपासना स्थल की धररुडड डररुकुतल के डरवररुतन के संबंघ डें कुसी डी नुडरडरलडड के डडकुष लंबतल कु डी डु कुडडर डर कानुनी कारुडरवरडी डडरडतु हु आडगी और कु डी नडर डु कुडडर डर कानुनी कारुडरवरडी शुरु नरुड की आडगी ।

##### अधनलडड के अपवरड (धरर 5):

- ड यह अधनलडड डररुडीन और डेतहरसकु डडररकु, डुररतलतुतवकु स्थलु तथर **डररुडीन डडररकु एवं डुररततुतव स्थल अवशुष अधनलडड, 1958** के अंतरगत आने वरले अवशुषु डर लागू नरुड हुतु है ।
- ड डरडले डी इसडें शरडलल नरुड है डु डरले हरलरगू हु कुके है डर सुलडु हुड है और इस तरह के वरवरुडु डें सडुधरंत लागू हुने सेडरले तड कडुडु गड रूडरंतरण शरडलल है ।
- ड यह अधनलडड अडुधुडर डें डरड डनुडडुडरडर डररुडड डररुडड के नरड से डररुडरने डरने वरले वशषलतु उपासना स्थल तक वसुतररतल नरुड है, डरसडें इससे डुडु कु डी कानुनी कारुडरवरडी डी शरडलल है ।

##### दंड (धरर 6):

- ड यह धररर अधनलडड का उललंघन करने डर अधकुतड तलन वरुष की कुड और डुरुडरने सहतल दंड नरुडडलतु करतल है ।

#### आलुओनर:

##### नुडरडकु डडरकुषर डर रोक:

- ड आलुओकुु का तरुकु है कु अधनलडड **नुडरडकु डडरकुषर** कु रोकता है, डु संवधलन का एक डुलडुत डरलु है ।
- ड उनका डरननर है कु डरड डरतडडध नरुडतरुण और संतुलन डरणरली कु कुडडुडर करतर है तथर संवेधरनकु अधकुडररु की रकुषर डें नुडरडडरलकु की डुडकुडर कु सीडतल करतर है ।

##### डुरववुडरडु कडऑऑ तथलः

- धार्मिक स्थलों की स्थिति निर्धारित करने के लिये एक **मनमानी तथि (स्वतंत्रता दविस, 1947)** का उपयोग करने के लिये इस अधिनियम की आलोचना की जाती है।
- वरिधियों का तर्क है कयिह **अंतिम तथि ऐतिहासिक अन्यायों की उपेक्षा करती है और उस तथि से पहले अतिक्रमणों के नविवरण को अस्वीकृत करती है।**
- **धर्म के अधिकार का उल्लंघन:**
  - आलोचकों का दावा है कयिह अधिनियम हटुओं, जैनियों, बौद्धों और सखिों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
  - उनका तर्क है कयिह **उनके उपासना स्थलों पर दावा करने और पुनरस्थापित करने की उनकी क्षमता को प्रतबिंधित करता है** जसिसे धर्म का पालन करने की उनके अनुयायियों की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होती है।
- **धर्मनरिपेक्षता का उल्लंघन:**
  - इस अधिनियम का वरिध करने वालों का तर्क है कयिह **अधिनियम धर्मनरिपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अधिक महत्त्व/प्राथमिकता प्रदान करता है।**
  - उनका तर्क है कयिह **कानून के तहत सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की भावना को कमजोर करता है।**
- **अयोध्या वविद मामले को अलग रखा जाना:**
  - अयोध्या वविद मामले को अलग रखा जाना भी इस अधिनियम की आलोचना का एक अन्य कारण है।
  - इस अधिनियम का वरिध करने वाले इसकी नरितरता पर सवाल उठाते हैं और धार्मिक स्थलों के साथ हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं।
- **अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख:**
  - **उपासना स्थल अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान की धर्मनरिपेक्षता के प्रतिप्रतबिद्धता को बनाए रखने वाले एक वधायी कार्रवाई के रूप में देखता है।**
  - यह अधिनियम सभी धर्मों के बीच समानता सुनिश्चित करने के राज्य के संविधानिक दायित्व को लागू करता है। यह प्रत्येक धार्मिक समुदाय के उपासना स्थलों के संरक्षण की गारंटी देता है।

## आगे की राह

- मामले से संबंधित आलोचनाओं और कमियों को दूर करने के लिये उपासना स्थल अधिनियम की गहन समीक्षा कयि जाने की आवश्यकता है।
- यह सुनिश्चित कयिा जाना चाहिये कयिह **अधिनियम संविधानिक अधिकारों को बनाए रखने में न्यायपालिका की भूमिका को संरक्षित करते हुए न्यायिक समीक्षा को प्रतबिंधित नहीं करता है।**
- **धार्मिक वशिष्टता के संरक्षण और वभिन्न समुदायों के अधिकारों का सम्मान करने के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है।**
- नषिपक्षता और स्थरिता को बढ़ावा देने के लिये सार्वजनिक परामर्श को शामिल कर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ ही वशिष्ट साइट्स के मामले को इस अधिनियम से अलग रखे जाने के कारणों की समीक्षा की जानी चाहिये।

## स्रोत: द हट्टि